RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 15 NOVEMBER TO 21 NOVEMBER 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 9 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

रिपोर्ट में खुलासाः पाकिस्तान ने यूक्रेन को 3000 करोड़ के हथियार बेचे

Page 2

अक्टूबर में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा देश का व्यापार घाटा

Page 3

कोरोना खत्म नहीं हुआ, इस ठंड फिर कोविड से कराह सकता है चीन, विशेषज्ञों की चेतावनी जानें

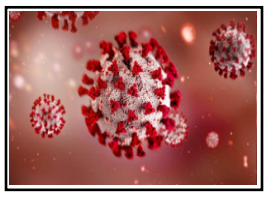

Page 4

editoria!

फिर जहरीली हुई हवा

पिछले सप्ताह हुई बारिश से बदले मौसम के मिजाज ने राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण से जो राहत दी थी, वह दिवाली तक ही रही। दिवाली के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में सांस लेना वैसे ही मुश्किल हो गया है जैसा आम तौर पर इस मौसम में होता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस साल दिवाली पर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में पिछले साल दिवाली के मुकाबले क्रमशः 45 और 33 फीसदी की बढ़ोतरी पाई गई। निश्चित रूप से इसके पीछे वे तमाम कारण हैं जिन पर बात लगातार होती रहती है, लेकिन इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा मुंह चिढ़ाती दिख रही है वह है दिवाली में हुई आतिशबाजी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी नीतियां बनाकर उन्हें सही ढंग से लागू करने के मामले में सरकारों की नाकामी निश्चित रूप से तकलीफदेह है, लेकिन इस बात का क्या करें कि पटाखों की बिक्री पर बैन होने के बावजूदऑनलाइन ऑर्डर देकर घरों पर पटाखे मंगाए गए और देर रात तक फोड़े जाते रहे। क्या ऐसा करने वालों को पता नहीं था कि अगले दिन उन्हें उनके साथ-साथ हजारों ऐसे लोगों को भी ये हवा अपने फेफड़ों में भरनी है जो अस्थमा या दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं? यह साल में सिर्फ एक बार कोई पर्व मना लेने भर का मामला नहीं है। यह बताता है कि एक समाज के रूप में हम आज भी कितने गैर-जिम्मेदार बने हुए हैं। हालांकि इन सबके बावजूद इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दिल्ली-ऍ में प्रदूषण की समस्या बनी रहने के पीछे दिवाली के पटाखों की सीमित भूमिका ही है। इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार पराली, बायोमास और कोयले को बताया जाता है। दिलचस्प है कि प्रदूषण का असर दिखना शुरू होने पर जब सरकार सक्रिय होती है, तब भी उसका ज्यादा जोर ऑड-ईवन लागू करने और कंस्ट्रक्शन रोकने जैसे कदमों पर होता है जबकि स्टडीज बताती हैं कि प्रदूषण में गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन डस्ट का योगदान 20 फीसदी ही होता है। सबसे ज्यादा भूमिका पराली जलाने के चलन की है। यहां भी सरकारी कोशिशें किसानों पर सख्ती करने की ओर केंद्रित दिखती हैं जबकि यह मूलतः टेक्नॉलजी से जुड़ी प्रॉब्लम है। असल में कंबाइन हार्वेस्टर का जो डिजाइन हमारे देश में इस्तेमाल होता है, वह कुछ इंच स्टबल छोड़ देता है। मगर ऐसे कंबाइन हार्वेस्टर भी उपलब्ध हैं, जो एकदम जमीन से फसल काट सकते हैं। क्या उन्हें नहीं आजमाया जा सकता? जहां तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण की बात है, उन पर काबू पाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाना होगा, साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी देनी होगी। इसके अलावा, ऐसे उपाय भी हैं, जिनके सहारे अन्य देशों ने अपने यहां की हवा को साफ करने में कामयाबी पाई है। जाहिर है, राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो हर साल आने वाली इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

तूफानी तेजी से भाग रही भारत की अर्थव्यवस्था

2028 में होगी तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी

नई दिल्ली। एजेंसी

इस समय भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। साल 2028 तक भारत की जीडीपी (Indian Economy) जापान को पीछे छोड़ देगी। मार्च 2024 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी (GDP) 6.2-6.3 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। अप्रैल-जून तिमाही में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 7.8 फीसदी रही थी। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2028 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (Indian Economy) वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका ही होंगे। भारत तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अभी आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की संभावना है।

क्या कहते हैं आंकड़े

आईएमएफ के मुताबिक, साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाल देश बन जाएगा। इस दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था 32.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर होगी। चीन की अर्थव्यवस्था 27.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर होगी। वहीं भारत 5.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वर्ष 2021 और 2022 में दो वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 वित्त वर्ष में भी निरंतर मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा है।

टॉप पर है अमेरिका

मौजूदा समय में अमेरिका 25,500 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन 18000 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरी और जापान 4200 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं भारतीय जीडीपी का आकार 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका था। बीते दिनों आए आईएमएफ और गोल्डमैन सैश के अनुमानों के मुताबिक साल 2075 तक भारत इकॉनमी के मामले में अमेरिका से भी आगे होगा। भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवतार में आए 'महाराजा', एयर इंडिया के लिए अब करेंगे ये काम

नई दिल्ली। एजेंसी

विमानन कंपनी एअर इंडिया और महाराजा का साथ बरसों पुराना है। महाराजा दशकों से एअर इंडिया की पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। विमानन कंपनी इस कनेक्शन को अब एक नया आयाम दिया है। एअर इंडिया के महाराजा को अब नए कलेवर में उतारा गया है।

महाराजा का ये नया अवतार

टाटा समूह की विमानन कंपनी ने जेनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंट लॉन्च किया है, जिसे महाराजा एआई नाम दिया गया है। इसके साथ ही एअर इंडिया दुनिया की पहली ऐसी विमानन कंपनी भी बन गई है, जिसने अपना जेनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंट लॉन्च किया है। कंपनी ने बताया है कि महाराजा एआई माइक्रोसॉफ्ट की एज्यूर ओपन एआई सर्विस से पावर्ड है।

मार्च में ही शुरू हुई थी टेस्टिंग

एअर इंडिया ने बताया है कि उसने इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग मार्च 2023 में शुरू की थी। कंपनी का दावा है कि नए अवतार में महाराजा ने अब तक 5 लाख से ज्यादा ग्राहकों के सवालों को हैंडल किया है। अभी महाराजा अपने एआई अवतार में हर रोज चार भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन में 6 हजार से ज्यादा सवालों को हैंडल कर रहे हैं।

... बस एक क्लिक पर इतिहास के 3.5 करोड़ पन्ने

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश की कुछ सबसे मूल्यवान पांडुलिपियों और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षक, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 3.5 करोड़ से अधिक पन्नों को डिजिटल कर दिया है। इन दस्तावेजों में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटेल के निजी कागजात भी शामिल हैं। एनएआई के महानिदेशक अरुण सिंघल ने हमारे सहयोगी न्यूजपेपर टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अभिलेखीय सामग्री को डिजिटल बनाने का उद्देश्य अनुसंधान कार्य या व्यक्तिगत रुचि के लिए उन्हें दुनिया भर में ऑनलाइन पहुंच योग्य बनाना है।

सिंघल ने कहा कि 70 लाख दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि हमें अगले दो वर्षों में 30.5 करोड़ पन्नों के डिजिटल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं को डाउनलोड करने पर मामूली शुल्क लिया जाएगा। सिंघल ने कहा कि बाकी काम के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पर 90 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। आसान पहुंच के लिए पुरालेख पोर्टल को ही नया रूप दिया जाएगा। सिंघल ने कहा कि सर्च इंजन एआई-आधारित होगा। इसमें रिसर्चर्स के लिए अन्य रिसर्चर के साथ दस्तावेजों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए प्रीमियम सुविधाएं होंगी।

एनएआई में निजी पत्रों के समृद्ध संग्रह में महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, एम आर जयकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के कागजात शामिल हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और मीनू मसानी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना की फाइलें और कनाडा, जर्मनी, मलेशिया, म्यांमार, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि से प्राप्त रिकॉर्ड भी हैं। सिंघल ने बताया कि ये प्राइवेट पेपर्स या तो किसी व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दान किए जाते हैं। इसलिए हम उनके नाम जोड़ते हैं और इसे एक निजी संग्रह कहते हैं। सार्वजनिक रिकॉर्ड विभिन्न सरकारी विभागों से आते हैं। इसके अलावा, हमें मुगल वंश के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ भी विरासत में मिले हैं। इनमें नूरजहां के फरमान भी शामिल हैं। अभिलेखागार में सबसे पुराने 6ठी शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें गिलगित पांडुलिपियाँ कहा जाता है।

डिजीटल संग्रह में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए इतिहास, वन और राजस्व मानचित्र और भारतीय और विदेशी मूल के अन्य मानचित्र और एटलस जैसे कार्टोग्राफिक दस्तावेज़ शामिल हैं। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए से संबंधित पर्याप्त कागजात भी थे। इन्हें आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। संग्रहीत सामग्री में फ़ाइलें, समाचार पत्र, रजिस्टर, नाममात्र रोल, फोटो एलबम, परीक्षण पत्र और कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ फ़ाइलें शामिल हैं जो आईएनए के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। ये पेपर शोधकर्ताओं के लिए जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक प्राथमिक स्रोतों में से हैं।

सिंघल ने बताया कि पहले, प्रति वर्ष 1.5 करोड़ पेज डिजिटल किए जाते थे। ऐसे में पूरी तरह से डिजिटलीकरण में 20 साल लग जाते थे। लेकिन अब हम प्रति वर्ष 15 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, यह कार्य कठिन है क्योंकि हमारे पास कागजों पर मौजूद 15इ वस्तुएँ इतनी नाजुक हैं कि उन्हें स्कैन नहीं किया जा सकता है। हमें उनकी मरम्मत करनी होगी और यह प्रक्रिया महंगी होने के साथ-साथ समय लेने वाली भी है। एक मरम्मतकर्ता प्रति माह दो तरफ वाली 1,000 शीटों को संभालने में सक्षम है। एनएआई महानिदेशक ने कहा कि वर्तमान में 50 मरम्मतकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रति वर्ष छह लाख शीटों की मरम्मत करते हैं। हमें अगले दो वर्षों में क्षतिग्रस्त रिकॉर्ड की मरम्मत के लिए लगभग 1,000 लोगों की आवश्यकता होगी। इसे डिजिटल बनाने के लिए प्रति शिफ्ट 500 वर्कर की आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट में खुलासा:

पाकिस्तान ने यूक्रेन को 3000 करोड़ के हथियार बेचे

रूस से सस्ता कच्चा तेल भी लेता रहा

एजेंसी

नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को घातक हथियार बेच रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को 36.4 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपये के हथियार बेचे हैं। साथ ही पाकिस्तान रूस से सस्ता कच्चा तेल और गेहूं लेता रहा और एहसान फरामोशी कर उसके दुश्मन को हथियार भी बेचता रहा। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को घातक हथियार बेच रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को 36.4 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपये के हथियार बेचे हैं। साथ ही पाकिस्तान रूस से सस्ता कच्चा तेल और गेहूं लेता रहा और एहसान फरामोशी कर उसके दुश्मन को हथियार भी बेचता रहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन को गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान ने बीते साल दो निजी अमेरिकी कंपनियों से हथियारों का सौदा किया था। रिपोर्ट में दावा है, ब्रिटिश सैन्य मालवाहक विमान ने युद्धग्रस्त देश को हथियार आपूर्ति के लिए रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के बेस नूर खान से साइप्रस, अक्रोटिरी और रोमानिया के लिए पांच बार उड़ानें भरीं। अमेरिकी फेडरल प्रोक्योरमेंट डाटा सिस्टम से करार का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 155 मिमी गोले की खरीद के लिए पाकिस्तान ने 17 अक्तूबर, 2022 को अमेरिकी कंपनियों ग्लोबल मिलिटरी से 1,926 करोड़ रुपये और नॉर्थरोप ग्रुम्मन के साथ 1,088 करोड़ रुपये का करार किया था, जो पिछले महीने खत्म हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, ये समझौते पीएम शहबाज शरीफ की सरकार के दौरान हुए थे। इसी गठबंधन ने बीते साल इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को हटाया था। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री से इन्कार किया। कहा, पाकिस्तान ने 'सख्त तटस्थता' की नीति अपनाई है।

बढ़ा हथियार निर्यात

रिपोर्ट में सबूतों के हवाले से बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश के हथियारों के निर्यात में 3,000 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पाकिस्तान ने 2021-22 में 107 करोड़ रुपये के हथियार निर्यात किए, जबकि 2022-23 में यह बढ़कर 3,447 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

Jio Airtel की होगी छुट्टी

स्टारलिंक सस्ते में देगा इंटरनेट

एजेंसी

जियो और एयरटेल की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि एलन मस्क की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट की मानें, तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे तो स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस काफी महंगी होती है, लेकिन भारत में इसे सस्ते में लॉन्च करने की तैयारी है, क्योंकि जियो और एयरटेल पहले से स्टारलिंक के मुकाबले को तैयार हैं। ऐसे में स्टारलिंक को सस्ते में लॉन्च किया जाएगा।

क्या है सैटेलाइट इंटरनेट?

यह एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जिसमें टॉवर और ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं होती है। इसमें पृथ्वी के लोअर आर्बिट में एक सैटेलाइट छोड़ा जाता है, जिसमें सैटेलाइट से सीधे पृथ्वी पर बिना तार इंटरनेट भेजा जाता है। आमतौर पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी को पहले तक मिलिट्री इस्तेमाल के तौर पर किया जाता है, लेकिन इस कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, उसे पृथ्वी तक पहुंचने में काफी वक्त लगता था, जिसे लेटेंसी रेट के तौर पर जाता है। इसे मिली सेंकेड में मापा जाता है। हालांकि आज के दौर में लेटेंसी रेट कम हुई है, जिससे सैटेलाइट से सीधे पृथ्वी पर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद मिल रही है।

जियो और एयरटेल भी रेस में

जियो और एयरटेल की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉन्च की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसे कॉमर्शियल और आम इस्तेमाल के लिए लॉन्च करने में वक्त लग सकता है। साथ ही इसे किफायती रखने की जरूरत होगी।

अक्टूबर में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा देश का व्यापार घाटा

नई दिल्ली। एजेंसी

अक्टूबर में एक्सपोर्ट के मुकाबले देश का इंपोर्ट इतनी तेजी से बढ़ा है कि देश का व्यापार घाटा ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। अक्टूबर में देश का एक्सपोर्ट मासिक आधार पर 2.6% गिरा है, लेकिन इंपोर्ट 20.8% बढ़ा है. इसकी वजह से देश का व्यापार घाटा बढ़कर 31.5 बिलियन डॉलर हो गया है।

देश का व्यापार घाटा ऐतिहासिक ऊंचाई पर

अक्टूबर में एक्सपोर्ट 6.2% सालाना बढ़कर $33.57 बिलियन रहा। अक्टूबर में इंपोर्ट 12.3% सालाना बढ़कर $65 बिलियन रहा। मासिक आधार पर एक्सपोर्ट 2.6ङ्ग गिरा, इंपोर्ट 20.8% बढ़ा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि इंपोर्ट में ये बढ़ोतरी सालाना आधार पर सोने के इंपोर्ट में 95% बढ़ोतरी की वजह से है. बर्थवाल ने कहा कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के बावजूद अक्टूबर में व्यापार प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने कहा 'अक्टूबर के व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि सुधार दिखाई दे रहे हैं, अगर ये स्थिर हो जाते हैं तो ये व्यापार के लिए अच्छा संकेत है'। अप्रैल-अक्टूबर 2023 के लिए, एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 7% की गिरावट आई, जबकि इंपोर्ट में सालाना आधार पर 8.95% की गिरावट आई. अप्रैल-सितंबर के बीच गुड्स एंड सर्विसेज के कुल एक्सपोर्ट में 1.61% की कमी होने का अनुमान है, जबकि इंपोर्ट में 7.4% की गिरावट आई है।

अधिकारियों को मोबाइल, लैपटॉप जारी करते समय निर्देशों का ध्यान रखें विभाग : वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्रालय ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से अधिकारियों को मोबाइल, लैपटॉप और ऐसे ही अन्य उपकरण जारी करने के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करने और व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के विपरीत किसी भी नीति को वापस लेने के लिए कहा है।वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने जुलाई में आधिकारिक कार्य के लिए भारत सरकार के पात्र अधिकारियों को मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या समान श्रेणियों के उपकरण जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

व्यय विभाग ने एक ताजा कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने इस संबंध में अपनी नीतियां जारी की हैं जो वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं हैं। व्यय विभाग ने कहा, 'मंत्रालयों/विभागों को इस विषय पर अपनी नीतियों को रोकने/वापस लेने और इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया जाता है।' जुलाई में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपये तक की कीमत वाले मोबाइल, लैपटॉप या इसी तरह के उपकरणों के हकदार थे, जिन्हें वे चार साल के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकते थे। उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी केंद्र सरकार के अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हकदार थे। अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों के मामले में स्वीकृत क्षमता के 50 प्रतिशत को ऐसे उपकरण जारी किए जा सकते हैं। उपकरण की कीमत के बारे में दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह एक लाख रुपये (कर सहित) हो सकती है। हालांकि, 40 प्रतिशत से अधिक मेक-इन-इंडिया (भारत में निर्मित) कलपुर्जों वाले उपकरणों के लिए कीमत सीमा 1.30 लाख रुपये (कर समेत) होगी।

धनतेरस पर विदेशी मुद्रा भंडार में 4.67 बिलियन डॉलर का इजाफा

590.78 अरब डॉलर पर आ गया फॉरेक्स रिजर्व

एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा जारी किया है. डेटा के अनुसार 3 नवंबर, 2023 तक विदेशी मुद्रा भंडार 4,672 बिलियन डॉलर के उछाल के साथ 590.783 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। विदेशी करेंसी एसेट्स में भी बड़ी उछाल देखने को मिली है. विदेशी करेंसी एसेट्स 4.392 बिलियन डॉलर बढ़कर 521.896 बिलियन डॉलर रहा है। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में उछाल जारी है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 200 मिलियन डॉलर के उछाल के साथ 46.123 बिलियन डॉलर रहा है। एसडीआर में 64 मिलियन डॉलर का उछाल रहा है और ये 17.975 बिलियन डॉलर रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जमा रिजर्व 16 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 4.789 बिलियन डॉलर रहा है। ये माना जा रहा है कि हाल के दिनों में भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ा है जिसके चलते विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखने को मिला है। इसका असर ये भी है कि इसके चलते भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का भी विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कच्चा तेल 80 डॉलर प्रति बैरल के नीचे जा खिसका है. सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कम डॉलर खर्च करने होंगे।

भारत पर मंडराया दो तूफानों का खतरा, बिपरजॉय से भी दोगुना खतरनाक हो सकता है 'मिधिली'

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ओडिशा के तटीय इलाकों में 45 किमी प्रति घंटे से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भविष्यवाणी की है और उनमें से एक के गंभीर चक्रवात में बदलने की संभावना है।

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो बाद में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बड़े तूफान के रूप में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से आंध्र प्रदेश तट के पास और आसपास हवाओं की गति बढ़ने की संभावना है. दो दिन – 15 और 16 नवंबर को हवाएं चलेंगी।

घ्ऊ के वैज्ञानिक उमाशंकर दाश ने मंगलवार को कहा कि दक्षिणपूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कम दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में बदलने से पहले पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। दाश ने बताया कि बाद में सिस्टम उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर फिर से मुड़ेगा और 17 नवंबर को ओडिशा तट से उत्तरपश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा।

IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD ने कहा है कि अगर और जब निम्न दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनकर डिप्रेशन में बदल जाता है, तो इसे 'मिधिली' कहा जाएगा। घ्ऊ ने मछुआरों को अगली सूचना तक 15 से 17 नवंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर को ओडिशा के कुछ तटीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी भविष्यवाणी की है। साथ ही कहा है कि अगले दिनों में इसकी तीव्रता बढ़ने की संभावना है और 16 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी। डाउन टू अर्थ के अनुसार, मौसम विज्ञानियों ने एक और वायु चक्रवाती परिसंचरण देखा है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों पर बना हुआ है। दक्षिण कोरिया के जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी के टाइफून रिसर्च सेंटर के अनुसंधान वैज्ञानिक विनीत कुमार सिंह ने कहा, इससे निम्न दबाव का क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है।

चिप की कमी से उबर गई है ऑटो इंडस्ट्री

कार इंश्योरेंस सेगमेंट में इसका क्या हो रहा है असर

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले कुछ महीनों से मोटर वाहनों (Motor Vehicles) की बिक्री में भारी बढ़ोतरी दिखी है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने दो दिन पहले ही अक्टूबर 2023 के लिए मोटर वाहनों की बिक्री का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले महीने पैसेंजर व्हीकल (PV), थ्री-व्हीलर, टू-व्हीलर और क्वाड्रिसाइकिल का कुल उत्पादन 26,21,248 यूनिट रहा। इस दौरान खास तौर पर यात्री वाहनों के लिए, इस सेगमेंट में साल-दर-साल (YoY) 15.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। मोटर वाहनों की बिक्री पर हमने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अंडरराइटिंग एंड क्लेम्स (प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी) के चीफ गौरव अरोड़ा से बातचीत की। पेश है इस बातचीत के संपादित अंशः-

इन दिनों मोटर वाहनों की बिक्री में तेज बढ़ोतरी हो रही है। इस हिसाब से इस सेगमेंट में इंश्योरेंस ग्रोथ भी हो रहा है। पिछले त्योहारी सीजन की तुलना में इस त्योहारी सीजन में कार सेगमेंट में इंश्योरेंस ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं?

वाहन पंजीकरण संख्या (VAHAN वेबसाइट के अनुसार) के अनुसार, सभी तरह के वाहनों में सालाना आधार पर 7% की ग्रोथ देखी गई है और प्राइवेट कार सेग्मेंट के लिए ग्रोथ 7.4% सालाना रही है। यह ग्रोथ प्रमुख तौर पर सामान्य मानसून की उम्मीद और अर्थव्यवस्था में ओवरऑल बढ़ोतरी के चलते है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पिछले एक साल में चिप की कमी की चुनौती को सफलतापूर्वक कम किया है या कह सकते हैं कि इस चुनौती से उबरने में कामयाब रही है और यह फैक्टर सालाना ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि हर साल त्योहारी सीजन के दौरान अपेक्षाकृत अधिक मांग के कारण वाहनों की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे मोटर इंश्योरेंस की संख्या भी बढ़ जाती है। इस साल त्योहारी सीजन में इसी तरह का रुझान दिखने की उम्मीद है।

रिपोर्ट से पता चला है कि ओईएम की कम बिक्री के कारण इंडस्ट्री दबाव में रहेगी। इस पर आपका क्या विचार है?

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में सभी तरह के वाहनों के पंजीकरण में 7 फीसदी की सालाना ग्रोथ हुई है। साथ ही ओईएम की बिक्री भी रुझान के अनुरूप रहने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में मोटर की बिक्री 15% तक गिरी है। यह पिछले कुछ महीनों के 17-23% से कम है। क्या आप देखते हैं कि यह ट्रेंड जारी रहेगा? जुलाई 2023 में संख्या में कमी सीजनल लग रही है। वित्त वर्ष 2023 में भी मंथली बेसिस पर इसी तरह की गिरावट देखी गई। जुलाई 2023 में अगर सालाना आधार पर देखें तो 10% से अधिक की ग्रोथ रही है।

इस त्योहारी सीजन के चलते इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या प्रभाव होगा? जैसा कि पहले ही बताया गया है, त्योहारी सीजन के दौरान नए वाहनों की मांग अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे इंश्योरेंस की संख्या बढ़ती है। मौजूदा फेस्टिव सीजन भी कुछ ऐसा ही रहने की उम्मीद है।

देश की सबसे बड़ी NBFC पर RBI का एक्शन, लोन पर लगाया ब्रेक, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली। एजेंसी

आरबीआई (RBI) ने देश की सबसे बड़ी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस (NBFC) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने इस एनबीएफसी को दो लेंडिंग प्रॉडक्ट्स के तहत लोन मंजूर करने और बांटने पर रोक लगाने को कहा है। इनमें ईकॉम (eCom) और इंस्टा ईएमआई कार्ड (Insta EMI Card) शामिल है। बजाज फाइनेंस के खिलाफ नियमों को नहीं मानने के कारण यह कार्रवाई की गई है। बजाज फाइनेंस मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। शुक्रवार के बंद भाव पर इसका मार्केट कैप 446,456.78 करोड़ रुपये है और यह देश की दसवीं सबसे मूल्यवान कंपनी है।

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन न करने, खासकर इन दो ऋण उत्पादों के तहत ग्राहकों को मुख्य तथ्यों का विवरण जारी न करने और कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल कर्ज के संबंध में जारी किए गए मुख्य विवरणों में खामियों के कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है।' बयान में कहा गया है कि उक्त कमियों को दूर करने और आरबीआई की संतुष्टि के बाद इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।

भारत के लिए MQ-9 ड्रोन कितना फायदेमंद, इस साल दो बार मार गिराया गया

वॉशिंगटन। एजेंसी

भारत अपनी थल सेना और नौसेना के लिए अमेरिकी एमक्यू-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा है। हाल में ही टू प्लस टू वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एमक्यू-9 रीपर ड्रोन के सौदे को लेकर भी बातचीत हुई थी। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को देखते हुए भारत को इस ड्रोन की बेहद सख्त जरूरत है। भारतीय नौसेना पहले से ही एमक्यू-9 रीपर ड्रोन की दो यूनिट को आपरेट कर रही है। लद्दाख गतिरोध के बाद से ये ड्रोन चीन सीमा के करीब भी उड़ान भर रहे हैं। इनके मिशनों ने भारतीय सेना को कई महत्वपूर्ण जानकारियां और ताजा हालात की अपडेट प्रदान की है। एमक्यू-9 रीपर ड्रोन को मध्य पूर्व में टेररिस्ट हंटर के रूप में ख्याति प्राप्त की है। लेकिन, एमक्यू-9 रीपर को हाल में मार गिराने की घटनाओं ने इसके संचालन की प्रासंगिकता के बारे में सवाल सामने ला दिया है।

एमक्यू-9 रीपर इतना शक्तिशाली क्यों

यह सवाल भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी सेनाओं के लिए एमक्यू-9 रीपर ड्रोन की खरीद पर काम कर रहा है, जबकि अमेरिकी वायु सेना इसे रिटायर करने की तैयारी में है। ऐसे में भविष्य के युद्धों में एमक्यू-9 रीपर ड्रोन की उत्तरजीविता पर सवाल उठ रहा है। अमेरिकी वायु सेना का इरादा 2035 तक एमक्यू-9 रीपर ड्रोन को चरणबद्ध तरीके से हटाने का है। अमेरिकी वायु सेना एमक्यू-9 रीपर को रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या आरपीए कहती है। एक रीपर लगभग ॅ-10 थंडरबोल्ट घ्ध जितना विशाल होता है। यह 3,750 पाउंड के हथियारों (आठ हेलफायर मिसाइलों) को ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे लगभग 2,000 मील की दूरी तय कर सकता है।

हजारों मील दूर से ऑपरेट हो सकता है एमक्यू-9 रीपर

यह दुनिया भर में घूम सकता है जबकि इसका ऑपरेटर हजारों मील दूर बैठा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमक्यू-9 रीपर कमांड सेंटर से उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है। एमक्यू-9 रीपर में स्टील्थ फीचर की कमी है, लेकिन पायलट रणनीति से उसकी भरपाई कर सकते हैं। हालांकि, भारतीय विशेषज्ञ एमक्यू-9 रीपर को हाल में हुए नुकसान को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स से बात करते हुए रिटायर्ड वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा ने कहा कि ड्रोन की इस श्रेणी में एमक्यू-9 सबसे अच्छा है। किसी भी सैन्य मंच को खरीदने के मानदंड को हमारे संदर्भ में देखा जाना चाहिए और जिस प्रतिद्वंद्वी का हमें सामना करना पड़ सकता है, उसमें देखा जाना चाहिए।

अमेरिका में महंगाई घटने से भारत में एफआईआई निवेश बढ़ने की उम्मीद

जानिए किन सेक्टर्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा

एजेंसी

अक्टूबर महीने में अमेरिका में रिटेल महंगाई के उम्मीद से भी कम रहने के कारण एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स और बीएसई सेंसेक्स 15 नवंबर को 1 फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं। महंगाई घटने से ये उम्मीद जगी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। बाजार जानकारों का कहना है कि आगे चलकर महंगाई में कमी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भारतीय इक्विटी बाजारों को और मजबूती प्रदान करेंगी जो पहले से ही मजबूत स्थिति में हैं। बता दें कि अक्टूबर में अमेरिकी रिटेल महंगाई दर गिरकर 3.2 फीसदी पर आ गई है। ये 3.3 फीसदी के अनुमान की तुलना में कम है।टोरस ओरो पीएमएस के फंड मैनेजर वैभव शाह का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती से शॉर्ट टर्म में घरेलू बाजार में तेजी आती दिखेगी। अब दुनियाभर में ब्याज दरों के अपने हाई पर पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा दिख रही हैं। यहां से दरों में कटौती शुरू हो सकती है। ऐसे होने पर भारतीय बाजारों में भारी मात्रा में विदेशी पैसा आता दिखेगा। इसी तरह. मध्यम से लंबी अवधि में कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं ग्रोथ के लिए संघर्ष करती दिख सकती हैं। लेकिन मजबूत फंडामेंटल्स और ग्रोथ के अनुकूल महौल के चलते इंडियन इकोनॉमी आउटपरफार्म करती नजर आ सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज पीएमएस के पोर्टफोलियो मैनेजर निशित मास्टर का कहना है कि भारतीय बाजार बहुत मजबूत स्थिति में हैं। दुनियाभर के बाजारों में फैली अस्थिरता और कमजोरी के बीच भारतीय बाजार स्थिरता और मजबूती के द्वीप जैसी स्थिति में दिख रहे हैं।

कोरोना खत्म नहीं हुआ, इस ठंड फिर कोविड से कराह सकता है चीन, विशेषज्ञों की चेतावनी जानें

बीजिंग। एजेंसी

चीन में इस सर्दी में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स अखबार के अनुसार, चीनी श्वसन रोग विशेषज्ञों ने सर्दियों में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने बुजुर्गों और कमजोर इम्यून वाली आबादी से जल्द से जल्द फिर से कोविड-19 टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार, पिछले महीने, चीन में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई है। यह तेजी काफी छोटी है, लेकिन इसे आने वाली सर्दी के मौसम के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अक्टूबर में चीन में कोविड-19 के कुल 209 नए गंभीर मामले सामने आए और 24 मौतें हुईं। सरकारी एजेंसी ने कहा कि मामलों की संख्या में बढ़ोतरी एक्सबीबी वेरिएंट के स्ट्रेन के कारण हुई है।

चीन में संक्रमण के बढ़ने का क्या कारण?

महामारी की शुरुआत के बाद से चीन ने बेहद सख्त जीरो कोविड पॉलिसी को लागू कर दिया। यह संक्रमण को रोकने के मामले में काफी हद तक सफल रही, लेकिन इसने चीनी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस कारण चीन ने दिसंबर 2022 में अचानक इस रणनीति को छोड़ दिया, जिस कारण देश को कोविड संक्रमण की भारी लहर का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि तब तक चीन की अधिकांश आबादी इस वायरस से संक्रमित नहीं हुई थी और इसलिए उनमें कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। विशेष रूप से, चीनी टीकों को बहुत महत्वपूर्ण तरीकों से संक्रमण को रोकने के लिए नहीं जाना जाता है।

चीनी लोगों में कोविड इम्यूनिटी का अभाव

चीनी वैक्सीन के कम प्रभावशीलता के कारण ओमीक्रोन और एक्सबीबी जैसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट अतिसंवेदनशील लोगों के एक विशाल समूह को संक्रमित करने में कामयाब रहे। यह संभव है कि यह संभव है कि चीन में लोगों के एक वर्ग ने अभी तक कोविड के विभिन्न प्रकारों के वेरिएंट्स के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित नहीं की है, जिससे पिछले महीने कोविड-19 के नए मामलों और मौतों में थोड़ी वृद्धि हुई है। अगले महीनों में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल सकता है।चीनी कोविड वैक्सीन की निष्क्रियता ने बढ़ाई टेंशन

दूसरा कारण उपयोग में आने वाले दो चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्मा की प्रभावकारिता हो सकती है। चीन के अधिकांश आंकड़ों की तरह, डिस्ट्रीब्यूट

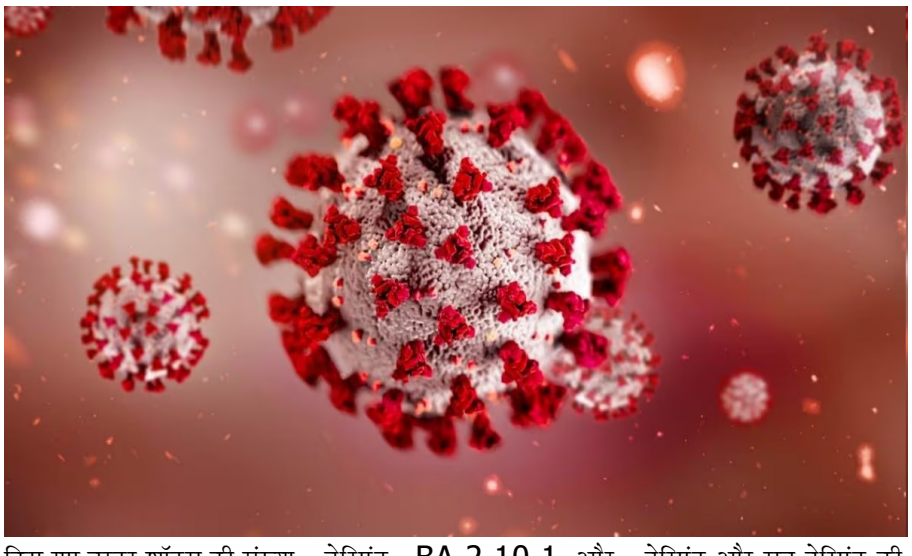

किए गए बूस्टर शॉट्स की संख्या पर अधिक स्पष्टता नहीं है। समय के साथ टीके लगातार कम प्रभावी होते जाते हैं, और बूस्टर के साथ-साथ प्राकृतिक प्रतिरक्षा दोनों के अभाव में, आबादी की सुरक्षा बेहद कमजोर हो जाती है।

एक्सबीबी कितना खतरनाक है?

XBB दो ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट, BA.2.10.1 और BA.2.75 का एक रिकॉम्बिनेशन है। कई अध्ययनों से पता चला है कि एक्सबीबी अधिक प्रतिरक्षा प्रतिरोधी है - यानी, यह टीकाकरण से मिलने वाली प्रतिरक्षा को चकमा दे सकता है। इससे डर है कि आने वाले दिनों में चीन के लोग कोरोना वायरस के कई दूसरे वेरिएंट और सब वेरिएंट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि उनका इम्यून अभी अन्य देशों के लोगों के मुकाबले काफी कमजोर है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वेरिएंट अधिक गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु का कारण बन सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी पर आई रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने 'ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023' की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है और टीबी मरीजों के इलाज का कवरेज 80% तक बढ़ गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में 'ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023' जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2022 में पूरी दुनिया में ट्युबरकुलोसिस (टीबी) के 75 लाख मामले आए, ये मामले अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं।

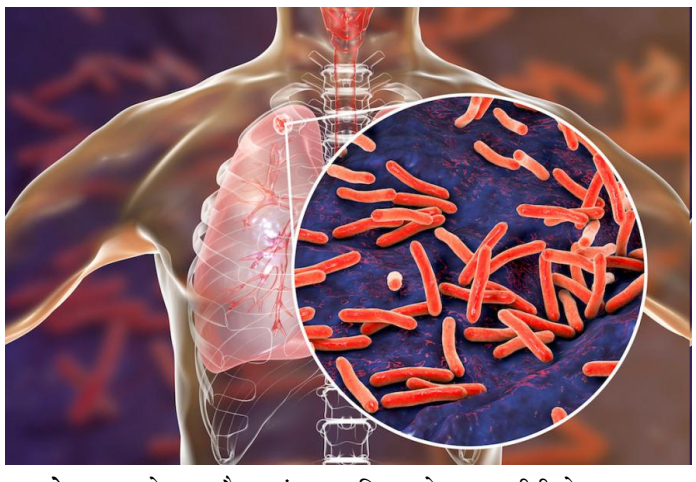

'ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023' के अनुसार भारत में साल 2022 में टीबी के 28.22 लाख मामले दर्ज किए गए। जिसका मतलब है कि दुनिया में ट्युबरकुलोसिस के कुल मामलों में से 27 फीसदी मामले सिर्फ भारत में हैं। आसान भाषा में समझे तो दुनिया के कुल टीबी मरीजों का हर चौथा मरीज भारत में है और भारत में हर 1 लाख की आबादी में से 210 लोग टीबी से संक्रमित हैं।

हालांकि, इस आंकड़े के बावजूद अगर इसकी तुलना साल 2021 के आंकड़े से की जाए तो पिछले साल की तुलना में साल 2022 में टीबी के मरीजों की संख्या में एक प्रतिशत की कमी आई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार टीबी के मरीजों के इलाज की पहुंच के मामले में साल 2022 में भारत में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही यह भारत दुनिया के उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां 80 प्रतिशत से ज्यादा टीबी के मरीजों तक इलाज पहुंच पा रहा है।

सरकार की मानें तो साल 2021 में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच की गई है। इस बीमारी के जांच के लिए भारत के अलग अलग राज्यों, शहरों और गांव में 4,760 से ज्यादा जांच मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी पहुंच हर जिले तक है।

टीबी से कितने लोगों की गई जान

इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के कारण होने वाली मौत के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में कमी आई है। साल 2021 में देश में इस बीमारी की चपेट में आकर 4.94 लाख लोगों ने अपनी जान गवाई थी, जबकि साल 2022 में ये आंकड़ा 3.31 लाख का हो गया है। यही कारण है कि दुनियाभर में इस बीमारे से हुई मौतों में भारत का मृत्यु दर योगदान 36 से घटकर 26 प्रतिशत पर आ गया है।

अपने लक्ष्य के कितने करीब है यह भारत

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से देश में टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए साल 2025 तक का लक्ष्य रखा है। अभी इस लक्ष्य को पूरा करने में 3 साल शेष है लेकिन अगर भारत इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहता है तो साल 2025 तक हर एक लाख जनसंख्या पर 44 से ज्यादा टीबी के मामले नहीं आने चाहिए। हालांकि, वर्तमान में जो मरीजों के आंकड़े आ रहे हैं उससे इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि यह देश फिलहाल 2023 के लक्ष्य के हिसाब से भी पीछे चल रहा है। 2023 इस देश ने हर एक लाख लोगों पर 77 मरीज का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी 199 मामले सामने आ रहे हैं।

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कर रही है सरकार

साल 2018 से लेकर साल 2022 तक केंद्र सरकार ने टीबी के 71 लाख मरीजों को नि-क्षय पोषण योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा पिछले साल 1 करोड़ 40 लाख जांच और 58 लाख न्यूक्लिक एसिड एम्पिलिफिकेशन टेस्ट किए गए हैं। साल 2020-2021 के दौरान, भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (ॐ) के जरिए टीबी रोगियों को 670 करोड़ रुपये की राशि दी है। साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया गया है।

क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) ?

ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती है. धीरे-धीरे ये दिमाग या रीढ़ सहित शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है। टीबी की बीमारी की शुरुआत माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। शुरुआत में तो शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे-जैसे यह संक्रमण बढ़ता जाता है, मरीज की परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों के शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें टीबी का खतरा ज्यादा रहता है।

ये बैक्टीरिया शरीर में कैसे प्रवेश करता है

टीबी का बैक्टीरिया शरीर में खांसने या छींकने से हवा के जरिए प्रवेश करता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली छोटी-छोटी बूंदों के जरिए अन्य लोग प्रभावित हो सकते हैं। फेफड़ों के अलावा टीही ब्रेन, यूटरस, मुंह, लिवर, किडनी या गले में भी हो सकती है। लेकिन फेफड़ों में होने वाली टीबी से ही खांसने या छींकने के जरिए बीमारी फैलती है। एक्सपर्ट की मानें तो फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों में टीबी के संक्रमण को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है और टीबी की बीमारी किसी भी अंग में हो सकती है।

इस बीमारी से बचने का तरीका

बीमारी से दूर रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूक होना। अगर आप टीबी के मरीज हैं तो मरीजों को समय-समय पर जांच कराने की सलाह दी जाती है क्योंकि टीबी का सही समय पर इलाज ना होने पर बीमारी गंभीर हो जाती है। टीबी की गंभीर स्थिति में दवा लेने पर भी काम नहीं करती।

सूर्यास्त के बाद घर में मिले ये संकेत तो समझिए बरसने वाली है मां लक्ष्मी की कृपा

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

लक्ष्मी जी का वास जिस घर पर होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती. ज्योतिष के अनुसार मां लक्ष्मी के आगमन से पहले कुछ शुभ संकेत मिलते हैं. खासकर सूर्यास्त के बाद ये संकेत मिलना शुभ होता है.

लक्ष्मी जी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है. इसलिए जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहां कभी आर्थिक तंगी नहीं रहती. लेकिन मां लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है. इसलिए वह एक स्थान पर विराजमान नहीं रहतीं. मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए कई उपाय बताए गए हैं.

हर व्यक्ति अपने घर पर मां लक्ष्मी का वास चाहता है. लेकिन

अपने आगमन से पहले मां लक्ष्मी कुछ संकेत देती हैं. यदि आपको भी ये संकेत मिले, तो समझिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होने वाला है. आइये जानते हैं इन शुभ संकेतों के बारे में.

चिड़िया का घोंसला: घर पर चिड़िया का घोंसला बनाना भी शुभ संकेत है. इसका मतलब है कि, जल्द ही आपको कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है.

सपने में इन चीजों को देखना: सपने में झाड़ू, शंख, सांप, छिपकली, उल्लू, बांसुरी, कमल या गुलाब के फूल, घड़ा आदि जैसी चीजों को देखना भी अच्छा माना जाता है. ऐसे सपने धन प्राप्ति का संकेत होते हैं.

काली चींटियों का झुंड: घर पर काली चींटियों का झुंड नजर आना बहुत शुभ माना जाता है. यदि काली चीटिंयों का झुंड दिखाई दे तो उन्हें नुकसान न पहुंचाएं. बल्कि आटा या चीनी जैसी चीजें खाने के लिए दें. काली चींटियों का झुंड इस बात का संकेत है कि, मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको उनका आशीर्वाद मिलने वाला है.

छिपकली का दिखना: छिपकली को देखकर लोग डर जाते हैं. लेकिन घर पर छिपकली का दिखाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है. खासकर सूर्यास्त के बाद घर पर एक साथ तीन छिपकलियां दिखाई देना मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत होता है.

इस दिन से होगी छठ पूजा की शुरुआत

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है. इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है. यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है. उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. चार दिनों तक चलने वाले छठ की शुरुआत नहाय खाय के साथ होती है. छठ पूजा का व्रत संतान की दीर्घायु,सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए किया जाता है. महिलाएं छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं. आइए जानते हैं इस साल कब से शुरू हो रही है छठ पूजा और सूर्योदय का समय क्या है.

छठ पूजा का पहला दिन

नहाय-खाए- 17 नवंबर

दीवाली के चौथे दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय- खाए की परंपरा निभाई जाती है. इस दिन कुछ विशेष रीति रिवाजों का पालन करना होता है. इस बार 17 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत होगी. इस दिन घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है. इसके बाद छठव्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं. नहाय खाय में व्रती सहित परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी, चने की दाल, मूली आदि ग्रहण करते हैं. व्रती के भोजन करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं.

छठ पूजा का दूसरा दिन

खरना- 18 नवंबर

दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिनभर का उपवास रखते हैं. इस दिन को खरना कहा जाता है. इस दिन सुबह व्रती स्नान ध्यान करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं. अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है. शाम को पूजा के लिए गुड़ से बनी खीर बनाई जाती है. इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है.

छठ पूजा का तीसरा दिन

डूबते सूर्य को अर्घ्य- 19 नवंबर

कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि होती है. व्रती इस दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं. बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है. इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर जाती हैं. संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है.

सूर्यास्त का समयः शाम 5 बजकर 26 मिनट.

छठ पूजा का चौथा दिन

उगते सूर्य को अर्घ्य- 20 नवंबर

चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इस दिन सूर्योदय से पहले ही भक्त सूर्य देव की दर्शन के लिए पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं. अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं.

सूर्योदय का समयः सुबह 6 बजकर 47 मिनट पर

तुलसी विवाह के दिन ये उपाय करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं होती हैं खत्म

कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है. इस मास में भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं. शास्त्रों में कार्तिक मास में तुलसी विवाह पर्व का विशेष महत्व बताया गया है. कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी होती है. इस दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. इस साल तुलसी विवाह का पर्व 24 नवंबर, शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा. इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं.

सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें ये उपाय

अगर आपके वैवाहिक जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही हैं तो तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय जरूर करें. इसके लिए पति-पत्नी को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए. अगर यह सम्भव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल या किसी पवित्र नदी का जल मिलकर स्नान कर लें. ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच चल रहा मनमुटाव खत्म होता है.

तुलसी के पत्तों को साफ पानी में डालें और कुछ देर रखने के बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें. माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है.

तुलसी के पत्ते को कभी भी एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए. तुलसी के उपाय करने के लिए हमेशा इसके 2-3 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर लें या अपने आप टूट कर गिरे पत्तों का इस्तेमाल करें. इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है.

तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र और सोलह श्रृंगार अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है. इस दिन पति-पत्नी को एक साथ तुलसी विवाह में भाग लेना चाहिए. इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.

तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह रचाने से वैवाहिक जीवन में मिठास घुलती है. इससे जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है.

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

अगर आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह ना भी करा पाएं तो जहां भी तुलसी विवाह हो रहा हो वहा जाएं या फिर मंदिर में जाकर तुलसी माता को लाल चुनरी और सोलह श्रृंगार अर्पित करें. इससे वैवाहिक जीवन में चल रही खटपट दूर होती हैं.

घर की सुख-शांति नष्ट करते हैं ये पेड़-पौधे, भूलकर भी ना लगाएं

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

वास्तु शास्त्र में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का खास महत्व होता है. इसके अनुसार घर में रखी हर चीज व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डालती है. वास्तु में हर एक सामान से लेकर पेड़-पौधे तक रखने की एक निश्चित दिशा बताई गई है. वास्तु के इन नियमों का पालन ना करने पर घर के सदस्यों के इसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ पेड़-पौधे गलती से भी नहीं लगाने चाहिए. इन पौधों को लगाने से घर में दुर्भाग्य और कंगाली आती है. आइए जानते हैं कि घर में कौन से पेड़-पौधे गलती से भी नहीं लगाने चाहिए.

घर में गलती से ना रखें ये पेड़-पौधे

घर के आंगन में भूलकर भी खजूर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए. ये अशुभ माना जाता है. यह पेड़ दिखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन माना जाता है कि इसे लगाने से घर के सदस्यों पर कर्ज बढ़ता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, ये घर में नकारात्मकता लाता है. इसे लगाने से घर में हमेशा डर और भय का माहौल बना रहता है. इसलिए इसे भी घर में नहीं लगाना चाहिए. घर में पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए. वास्तु के अनुसार इसे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है. अगर घर की दीवार या किसी कोने में पीपल का पौधा उग आया है तो उसे निकाल कर हटा देना चाहिए. घर में लगाए गए कोई भी पेड़-पौधे अगर सूख रहे हों तो उसे हटा देना बेहतर रहता है. वास्तु के अनुसार सूखे पेड़-पौधे घर में उदासी लाते हैं और इन्हे लगाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है.

आज के दौर में घर में सजावट के लिए बोनसाई के पौधे रखने का चलन बढ़ गया है. ये पौधे दिखने में जरूर खूबसूरत होते हैं लेकिन इसे घर में रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ये तरक्की में रुकावट बनते हैं. मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी शक्तियों का वास होता है और इस पौधे को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. ये पौधा घर की सुख-शांति को भंग करता है. शास्त्रों के अनुसार घर में बबूल का पौधा लगाने से वाद-विवाद बढ़ता है. इससे परिवार के सदस्य मानसिक तौर पर बीमार रहने लगते हैं. इसका घर के आसपास होना भी अशुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र में घर के अंदर और आसपास की जगहों पर कभी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए. इससे घर में तनाव का माहौल रहता है. ऐसे पौधे आपसी मतभेद बढ़ाने का भी काम करते हैं. कई बार लोग अनजाने में इन पौधों को लगा लेते है जो आगे चलकर बर्बादी का कारण बनते हैं.

एक्सपोर्ट डिमांड में मजबूती, जीरे की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी की उम्मीद

नई दिल्ली। एजेंसी

अक्टूबर के हाई से तेज गिरावट के बाद अब जीरे की कीमतों के फिर से तेजी पकड़ने की उम्मीद दिख रहीं है। जीरे की डिमांड में बढ़त दिख रही है। जिससे आने वाले महीनों में जीरे की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस मसाले के दो सबसे बड़े उत्पादक गुजरात और राजस्थान में नए सीज़न के लिए बुआई प्रगति पर है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जीरे की निर्यात मांग में कमी देखने को मिली थी। जून- अक्टूबर 2023 की अवधि में जीरे की कीमतें एक साल पहले की तुलना में 100-200 फीसदी बढ़कर 500-700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थीं। भारत जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो मिर्च के बाद देश से निर्यात होने वाला दूसरा सबसे बड़ा मसाला भी है।

जून-अक्टूबर 2023 में जीरे की कीमतें 100-200 फीसदी बढ़कर 500-700 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। फसल की बुआई में कमी और गुजरात में मार्च-अप्रैल के दौरान फसल कटाई के समय बेमौसम बरसात के चलते जून- अक्टूबर 2023 में कीमतें आसमान पर पहुंचती दिखी थी। जीरे की कीमतों में बेतहाशा बढ़त के चलते एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ा था। मसाला बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-अगस्त 2023 में एक्सपोर्ट की मात्रा पिछले साल की समान अवधि से 24 फीसदी घटकर 69,779 टन रह गई थी।

हालांकि कीमतों के चलते एक्सपोर्ट घटने को बावजूद निर्यातकों की कमाई पर असर नहीं पड़ा था। एक्सपोर्ट घटने को बावजूद निर्यातकों की कमाई में 26 फीसदी की बढ़त हुई और यह 2,426 करोड़ रुपये पर रही। वित्त वर्ष 2023 में जीरा निर्यात 1.86.508 टन तक पहुंच गया। जिसकी कीमत 4.194 करोड़ रुपये रही थी।

जीरे की कीमतों में गिरावट

लेकिन वर्तमान में गुजरात और राजस्थान में नई फसल की बुआई बढ़ने से जीरे की कीमतें अब तक के हाई से गिरकर लगभग 450 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं। हालांकि कीमत अभी भी पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। इस बीच निर्यात मांग फिर से बढ़ गई है। वीजे इंटरनेशनल के मालिक और एक्सपोर्टर मयूर वाघानी का कहना है कि सीरिया और तुर्की जैसे दूसरे जीरा उत्पादक देशों में स्टॉक खत्म हो गया है। ग्लोबल लेवल पर इस समय भारत इस मसाले का अकेला सप्लायर है। कीमतें गिरने के साथ ही इस समय एक्सपोर्ट के लिए काफी पूछ-ताछ हो रही है। इस साल जीरे की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई। जिसके चलते नए सीजन में इसका रकबा बढ़ने की उम्मीद है। जिसका नुकसान धनिया को उठाना पड़ सकता है। बता दें की गुजरात और राजस्थान में धनिया भी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जीरा और धनिया दोनों काफी अहम मसाले हैं जिनकी घरेलू बाजार में अच्छी मांग है। करी पाउडर बनाने वालों में इनकी भारी मांग होती है।

धवल एग्री एक्सपोर्ट्स के सीईओ जय चंद्राना का कहना है कि अगले सीज़न में जीरे का रकबा ज्यादा रहने की उम्मीद है। इसका नुकसान धनिया को हो सकता है। यानी जीरे का रकबा बढ़ने से धनिया का रकबा घट सकता है। बता दें धनिया की कीमतों में इस साल गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जब तक जीरे की बुआई काफी ज्यादा नहीं होती तब तक जीरे की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे गिरना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इपोर्टर कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि जीरे की कीमतें मौजूदा स्तर पर स्थिर हो सकती हैं।

वर्तमान स्टॉक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं

वघानी का कहना है कि 9-10 लाख बैग (55 किलोग्राम प्रति बैग) का मौजूदा स्टॉक अगली फसल तक की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। खासकर उस स्थिति में जब पश्चिम एशियाई देशों से रमजान की मांग दिसंबर-जनवरी तक शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अगले कुछ महीनों में 12-14 लाख बैग की जरूरत हो सकती है। इसमें से कम से कम आधा निर्यात के लिए और बाकी घरेलू बाजार के लिए होगा। वघानी को लगता है कि मजबूत मांग के चलते जीरे की कीमतें 500 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर जा सकती हैं।

आपकी कार को साइबर हमलों से बचाएगी सरकार, आ रहा है सुरक्षा कवच

नई दिल्ली। एजेंसी

लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए सरकार अब वाहनों को भी इन हमलों से बचाने की योजना पर काम कर रही है। वाहन निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे साइबर हमलों से वाहनों को सुरक्षित करने के लिए पैसिंजर और माल ढोने वाले वाहनों में साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाएं। इटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए ड्रॉफ्ट तैयार किया है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि अगले महीने की शुरुआत तक इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बताया गया है कि यह सिस्टम गाड़ियों के डेटा को हैकिंग से बचाने में मदद करेगा।

क्या करना होगा?

ड्रॉफ्ट के मुताबिक सभी वाहन निर्माताओं को वाहनों में एक साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाना होगा। वाहनों की मंजूरी के समय इसके लिए प्रमाण पत्र पेश करना होगा। यह सभी एम और एन कैटिगरी के वाहनों पर लागू होंगे, जिसमें पैसिंजर वाहन और अच्छे गुड्स कैरियर के साथ-साथ ट्रैक्टर भी शामिल हैं यदि उनके पास एक भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है।

क्यों है जरूरत?

अधिकारी का कहना है कि ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर मॉडर्न वीइकल्स ऑटोनॉमस ड्राइविंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड सर्विसेज जैसी अडवांस्ड टेक्नॉलजी से लैस हैं।

क्या है चुनौती?

अधिकारी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी साइबर हमलों और साइबर सिक्योरिटी की घटनाओं के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं। संभावित साइबर खतरों में बैक-एंड सर्वर की हैकिंग, वाहन द्वारा मिले संदेशों या डेटा की चोरी, वाहन डेटा या कोड का हेरफेर और वाहन कनेक्टिविटी में हेरफेर शामिल हैं।

सरकार की दलील?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च में संसद में कहा था कि भारत में साइबर सिक्योरिटी की घटनाओं पर नजर रखने और उनकी निगरानी करने वाली भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (ण्ऊ-घ्ह) को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों से रिपोर्ट मिली है। सरकार हैकिंग के मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठा रही है। सरकार का प्रस्तावित कदम तय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जिसके लिए सभी मैन्युफैक्चरर्स और उनकी सप्लाई चेन को वर्तमान और भविष्य के साइबर हमलों से बचाने के लिए मल्टी-लेयर साइबर सिक्योरिटी समाधान शामिल करने की आवश्यकता है।

सीएनजी कारें 2030 तक भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए तैयार

ईवी की क्रांति के बीच टाटा मोटर्स का रणनीतिक कदम

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

ऑटोमोबाइल बनाने वाली भारत की अग्रणी कंपनी टाटा मोटर्स ने सीएनजी वाहनों को ज्यादा वांछनीय और व्यावहारिक बनाकर एक साहसिक कदम उठाया है। अपनी ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ, टाटा मोटर्स ने सुनिश्चित किया है कि सीएनजी से पावर्ड वाहनों को हल्के में न लिया जाए। यह रणनीतिक कदम स्थायित्व के लिये टाटा मोटर्स की प्रतिबद्धता दिखाता है और साथ ही देश में सीएनजी वाहनों की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता पर इसकी समझ को जाहिर करता है। पिछले तीन से चार वर्षों में सीएनजी कारों को उल्लेखनीय आकर्षण मिला है, खासकर पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में। इसके दो महत्वपूर्ण कारक हैं- तरह-तरह के मॉडल्स की पेशकश और विस्तार कर रहा बुनियादी ढांचा। भारतीय बाजार में अब सीएनजी के मॉडलों की एक विविधतापूर्ण श्रृंखला है, अलग-अलग बॉडी टाइप्स और कीमतों में लगभग 17-18 वैरिएंट्स हैं, जिनकी पेशकश ओरिजिनल इक्विपमेंट के कई उत्पादक (ओईएम) कर रहे हैं। पेट्रोल वाले वाहनों की तुलना में भी कीमत बहुत अलग है, जिससे कि सीएनजी वाहनों के मालिकों के लिये परिचालन का खर्च लगातार कम होता है। देशभर में सीएनजी की रिफ्यूलिंग के स्टेशंस बढ़ने से स्थिति में बदलाव हुआ है। तीन साल पहले लगभग 1,500 स्टेशंस थे, जिनकी संख्या अब करीब 5500 पहुंच गई है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने उल्लेखनीय ढंग से सीएनजी वाहनों को अपनाया है और वहाँ के बाजारों में ऐसे वाहनों की पहुँच बढ़ी है। इन दो कारकों ने सीएनजी सेगमेंट की शानदार तरक्की में योगदान दिया है और तीन वर्षों में कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) को 35% पर पहुँचाया है, जबकि सालाना वृद्धि दर 52% हो चुकी है। पिछले साल में ही बाजार में 4 लाख सीएनजी कारों की बिक्री हुई, जिनमें से टाटा मोटर्स की लगभग 50,000 कारें थीं।

चाइनीज टैंक के जवाब में भारत का जोरावर, क्या है खासियत?

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत में डिजाइन और डिवेलप किए गए पहले लाइट टैंक का इस महीने के अंत में ट्रायल शुरू हो सकता है। यह टैंक ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चीन ने सीमा पर जिस तरह सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा कर रखा है, उसका जवाब देने में यह टैंक उपयोगी होगा।

द इकनॉमिक टाइम्स में मनु पब्बी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने यह लाइट टैंक रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया है। दिसंबर में इसके कई तरह के ट्रायल होंगे। इस टैंक के प्रोटोटाइप से जुड़ा काम पूरा होने वाला है। यह लाइट टैंक 25 टन कैटेगरी वाला है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर साल 2020 में चीन की हरकतों और उसके बाद ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में चीन की ओर से हल्के बख्तरबंद वाहनों को लाए जाने के बाद यह जरूरत महसूस की जाने लगी थी कि भारत को भी उस इलाके में लाइट टैंक की तैनाती करनी चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि भारत ने जो टैंक बनाया है, उसका नाम सेना ने फिलहाल जोरावर (Zorawar) रखा है। इस टैंक की खासियत यह है कि मोबिलिटी और ज्यादा सटीक फायर पावर के मामले में यह चाइनीज टाइप 15 टैंकों से बेहतर है। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर टाइप 15 टैंक तैनात किए हैं। भारत के 'जोरावर' टैंक में 105 मिलीमीटर की तोप लगी है। यह टैंक बनाने की मंजूरी अप्रैल 2022 में मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को पार्टनर बनाया था।

सूत्रों ने बताया कि पहले की रिपोर्ट्स से उलट इस टैंक का डिजाइन बिल्कुल नया है। इसकी चेसिस को पूरी तरह भारत में ही तैयार किया गया है। यह ख्ड्ड वड्ड्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन चेसिस पर बेस्ड नहीं है, जिसे भारत में पहले से बनाया जा रहा है। 'जोरावर' लाइट टैंक का वजन 25 टन रखा गया है ताकि यह बेहद दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में ज्यादा ऊंचाई पर भी काम कर सके। इसमें लगी 105 मिलीमीटर की तोप जॉन कॉकेरिल ने बनाई है। भारत में टैंक का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह तोप भी भारत में ही बनाई जा सकती है। इस टैंक में अनमैंड एरियल व्हीकल भी लगाया जा सकता है। इससे युद्ध के मैदान में इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। यह टैंक ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों सहित हर तरह के इलाके में काम कर सकेगा। तेजी से तैनाती के लिए इसे हवाई जहाज से भी ले जाया जा सकेगा।

इजरायल के साथ सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहता ईरान

तेहरान। एजेंसी

इजरायल के राजनेताओं और सेना के अफसरों ने हाल के दिनों में हिज्बुल्ला के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। इजरायल ने चेतावनी दी है कि अगर हिज्बुल्ला की ओर से हमले जारी रहे तो फिर कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इजरायल ने इशारा किया है कि वह हिज्बुल्ला के खिलाफ एक बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों ने इस पर जोर दिया है कि हिज्बुल्ला के समर्थक ईरान का इजरायल के साथ सीधे टकराव का कोई इरादा नहीं है। वहीं इजरायल भी इससे बचने की हरसंभव कोशिश करेगा।

गाजा पट्टी में हमलों के बाद से इजरायल के उत्तरी क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन हमले और घुसपैठ के प्रयास बढ़े हैं। पिछले सप्ताह में खासतौर से इनमें तेजी आई है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा है कि हम सुरक्षा के लिए जुटे हैं और उत्तर में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हलेवी ने इजरायल की उत्तरी सीमा पर पिछले दो दिनों में कई घटनाओं के बाद ये बयान दिया है। इसमें सोमवार को इजरायल पर दागे गए प्रोजेक्टाइल भी शामिल हैं, जिसमें दो नागरिक घायल हो गए। एक दिन पहले लेबनान की सीमा के करीब डोवेव के उत्तर में रविवार को हिज्बुल्ला के मिसाइल हमले में 14 इजरायली नागरिक घायल हो गए थे। जिनमें से एक की सोमवार को मौत हो गई। इसके बाद आईडीएफ बलों ने लेबनान में मिसाइल लॉन्चिंग साइटों पर हमला किया है।

हिज्बुल्ला भी लेकर चल रहा खास रणनीति

तेल अवीव में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के वरिष्ठ शोधकर्ता और लेबनान में विशेषज्ञता रखने वाली ओर्ना मिजराही ने अल-मॉनिटर से बातचीत में कहा है कि इजरायल फिलहाल हिज्बुल्ला के साथ पूरी तरह से युद्ध में शामिल नहीं है। फिलहाल संघर्ष सीमित है लेकिन एक महीने पहले की स्थिति की तुलना में चीजें बदल गई हैं। पिछले कुछ समय में तनाव निश्चित रूप से बढ़ा है। हिज्बुल्ला की मिसाइलें इजरायल के बहुत अंदर हाइफा के उपनगरों तक पहुंच रही हैं। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हिज्बुल्ला को इजरायल के खिलाफ एक बड़े अभियान में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को यह दिखाना है कि वह भी इजरायल के खिलाफ एक भूमिका निभा रहा है।

युद्ध जीत भी जाए फिर भी गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजरायल, अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिलाया भरोसा

ईरान को सीधे युद्ध में दिलचस्पी नहीं

आईएनएसएस के शोधकर्ता रज जिम्ट का कहना है कि ईरान को इजरायल के खिलाफ पूर्ण युद्ध में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह इजरायल के साथ टकराव के लिए हिज्बुल्ला को और ज्यादा सक्रिय करना नहीं चाहता है। वह इजरायल के खिलाफ जिस धुरी का नेतृत्व कर रहा है, उसमें सभी दलों की भागीदारी की सीमा से संतुष्ट है। जिम्ट का मानना है कि चीजें बदल सकती हैं अगर इजरायल अपने उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती वृद्धि को बर्दाश्त नहीं करता है या एक पक्ष दूसरे दूसरे पक्ष के इरादों का गलत अनुमान लगाता है।

जिम्ट का कहना है कि ईरान जो स्थिति पसंद करता है, उसमें इजरायल के खिलाफ हिज्बुल्ला का एक सीमित अभियान चलाया जाना है। जिसमें ईरान समर्थक मिलिशिया इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लगातार ऑपरेशन करना जारी रखते हैं। वहीं मिजराही का कहना है कि इजरायल अब तक हिज्बुल्ला के हमलों का जवाब देने और टकराव शुरू नहीं करने को लेकर सावधान रहा है। हालांकि हालिया समय में चीजें कुछ बदली हैं। पिछले चार हफ्तों में इजरायली गोलीबारी में 74 हिज्बुल्ला लड़ाके मारे गए हैं। मिजराही इस बात पर जोर देते हैं कि तनाव को रोकने के लिए इजरायल के लिए राजनयिक स्तर पर काम करना महत्वपूर्ण है।

लिंग बदलवाने विदेश जाने वालों के लिए अच्छी खबर

आएगी नई पासपोर्ट पॉलिसी, जानिए क्या है सरकार का प्लान

नई दिल्ली। एजेंसी

मान लीजिए कोई पुरुष या महिला अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने के लिए विदेश जाते हैं। ऐसे में वापस लौटते समय उसके नाम, लिंग और प्रेजेंस में परिवर्तन आ सकता है। ऐसे लोगों को पासपोर्ट (passport) से जुड़ी परेशानियां ना हो इसके लिए सरकार पॉलिसी विकसित करना चाहती है। हालांकि, सरकार ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट से समय मांगा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि उसे एक ऐसी पॉलिसी तैयार करने में समय लगेगा जो भारत से बाहर सेक्स चेंज सर्जरी कराने वाले लोगों को बिना किसी कठिनाई के नया पासपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाए।

बायोमीट्रिक रिकॉर्ड से हो वेरिफिकेशन

गृह मंत्रालय ने हाल ही में हाई कोर्ट को बताया कि उसने विदेश मंत्रालय को नई पॉलिसी बनाने की सलाह दी है। ऐसी पॉलिसी, जिसमें ऐसे भारतीय नागरिकों की पहचान बायोमीट्रिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है, जो पहले से ही अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं, क्योंकि ऐसे चिकित्सा प्रक्रियाओं के बाद बायोमीट्रिक नहीं बदलते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पॉलिसी बनाने से पहले विभिन्न हितधारकों और इसकी तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करने में उसे समय लगेगा।

ट्रांसजेंडर महिला ने डाली थी याचिका

सरकार का यह रुख एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर सामने आया है। इस महिला ने याचिका में बदले हुए नाम और लिंग के साथ उसका पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी, क्योंकि सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बाद उसकी प्रेजेंस बदल गई थी।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हालांकि पासपोर्ट जारी किया गया था और मामला निष्फल हो गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र से ऐसी पॉलिसी विकसित करने को कहा, जो देश के बाहर सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने वाले लोगों को अपनी नई पहचान में बिना किसी परेशानी के नया पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति दे। सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि एमएचए ने कहा कि इस मामले की जांच क्षेत्रीय एजेंसी के परामर्श से की गई है और चूंकि बायोमीट्रिक में बदलाव नहीं होने की संभावना है, इसलिए एमईए द्वारा एक सिस्टम या पॉलिसी विकसित की जा सकती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।